डेवेलपमेंट पर खर्च किया गया वह केवल सैलरीज आफ स्टाफ पर खर्च हुआ, सरकार के अपने आदमियों पर खर्च हुआ तथा अनएम्प्लायमेंट के प्रश्न पर विचार करते हुए, क्या सरकार ने अभी तक कम्यूनिटी डेवेलपमेंट ब्लाक्स में कोई ऐग्रो-इंडस्ट्रीज कायम की हैं और उन में अब तक कितने लोगों को एम्प्लायमेंट दिया गया है ? यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह होक्स कब तक चलाया जायगा ?

श्री जगजीवन राम : वास्तव में इस तरह से कहना कि बिल्कुल असफल हुआ है यह काम, कम से कम जिम्मेदार सदस्य से मैं ऐसी आशा नहीं करता था ।

श्री बलराज मधोक : मैंने पूछा है कि आपने कोई ऐग्रो-इंडस्ट्रीज कायम की हैं ?

श्री जगजीवन राम : मुझे जवाब तो देने दीजिये । जैसा बतलाया गया, कमेटियों ने जांच की है और इस का एवैलुएशन भी हुआ है । लाइब्रेरी में एवैलुएशन रिपोर्ट मिल जाएगी । सदस्य महोदय.....

श्री बलराज मधोक : मैं ने पढ़ा है ।

श्री जगजीवन राम : सदस्य महोदय उस को फिर पढ़ लें । उन्हें बहुत जानकारी मिल जायेगी । अब कहते हैं कि यह होक्स कब तक चलाया जायगा । मैं उन को कैसे समझाऊं कि यह सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । और वह चाहते हैं कि इस को न चलाया जाय, बन्द कर दिया जाये या उस में कुछ परिवर्तन कर के चलाया जाय, तो यह सारा काम तो राज्य सरकारों को करना है । माननीय सदस्य क्या ऐसा समझ लेते हैं कि हम इस के लिये बहुत ज्यादा उतावले हैं कि वह चलें ?

श्री बलराज मधोक : उन को बन्द कर दीजिये ।

श्री जगजीवन राम : वह बन्द हो सकते हैं, लेकिन यह भी समझना चाहिये कि बन्द करने का काम भी सिर्फ यहां से नहीं हो सकता है । सब कुछ राज्य सरकारों की राय से तय किया जाता है । लेकिन माननीय सदस्य को सब कुछ होक्स ही नजर आता है ।

Programme of sinking Tubewells in M.P.

+

*1293. SHRI NATHU RAM AHIRWAR :
SHRI LAKHAN LAL GUPTA:
SHRI MANIBHAI J. PATEL :
SHRI A. S. SAIGAL :
SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN :
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :
SHRI G. S. MISHRA :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh had informed his Ministry their requirement of imported rigs in connection with their programme of sinking 7,000 shallow tubewells for which his Ministry has also agreed to provide foreign exchange allocation ;

(b) if so, the countries from where rigs are required to be imported ;

(c) whether it is a fact that rigs of the type required by the Government of Madhya Pradesh will not be indigeneously available and that too in limited quantity before March, 1969 ; and

(d) if so, whether Government propose to issue instructions, to the Director General, Technical Development to accept the request of the Government of Madhya Pradesh for the import of a few rigs ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir. The Government of Madhya Pradesh has sought release of foreign exchange worth Rs. 30 lakhs for the import of 5 direct rotary-*cum*-down-the-hole rigs,

(b) U.S.A.

(c) and (d). The types of rigs mentioned above are not available immediately in the indigenous market. The Directorate General, Technical Development has, therefore, been requested to agree to their import from the indigenous angle.

श्री नाथूराम अहिरवार : जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बतलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को केवल पांच रिग्स बनाने की अनुमति प्रदान की है जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने 7,000 ट्यूब वेल खोलने की योजना बनाई है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि जितना व्यय होगा वह उसकी वहन करेंगे। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है जहां पर आज सिंचाई बहुत कम है। ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मध्य प्रदेश सरकार को अधिक रिग्स बनाने की अनुमति देने पर सरकार विचार करेगी ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : This foreign exchange is only in regard to those rigs which are not indigenously available. The other rigs, of many types, are available in the country and the State Government is free to purchase them.

श्री नाथूराम अहिरवार : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि प्रधान मंत्री का दौरा रूमानिया में हुआ था और रूमानिया की सरकार ने भारत सरकार को करीब 500 रिग्स देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि उससे अधिक भी मांगे जायेंगे तो वह भी देने के लिए तैयार हैं जिस का रुपी में पेमेंट करना होगा ? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : May I say that we are very sympathetic to the minor irrigation programmes of all the State Governments including Madhya Pradesh. But, as I have already mentioned, if the rigs are available in the country, naturally, in the national interests, we should not import those types.

श्री अ० सिं सहगल : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि हमने 30 लाख रुपया पांच रिग्स बनाने के लिए मंजूर किये हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जब रूमानिया सरकार और रशियन सरकार रिग्स देने के लिए तैयार हैं तब क्या आप मध्य प्रदेश की सरकार को, जो कि 7 हजार ट्यूबवेल बनाने के लिये तैयार है, ज्यादा रुपया देने की कृपा करेंगे ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I have already replied to this point.

श्री भारत सिंह चौहान : चूंकि मध्य प्रदेश एक आदिवासी क्षेत्र है और मध्य प्रदेश से एक योजना, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के पीने वाले पानी के लिये भेजी गई जो कि शासन ने मंजूर भी की है, इस दृष्टि से आदिवासी क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए साथ ही साथ कहां की संविद सरकार के साथ उदारता दिखाने के लिये जो रिग्स इम्पोर्ट करने का प्रश्न है उस पर सहानुभूतिपूर्वक ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जायेगा ? जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि जो चीज यहां बन रही है वह यहां की मांग के लिये काफी है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहां वह चीज नहीं बन रही है जो कि बाहर से आयात की जायेगी। इसलिये मध्य प्रदेश की जो मांग है क्या उसके बारे में आप इजाजत देंगे ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : To the second part, I have already replied. The first part, about drinking water, does not arise out of this.

श्री कं० ना० तिवारी : उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि दूसरे प्रान्तों में भी इन रिग्ज की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूँ कि दूसरे प्रान्तों से कितनी रिग्ज की मांग आई है और उस में कितनी फॉरेन एक्सचेंज खर्च होगी और कितनी सैंक्शन की गई है ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : If he gives notice, I shall reply.

श्री महाराज सिंह भारती : यह जो प्रश्न है यह कम गहरे नलकूपों के सम्बन्ध में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हजारों लोग बिना रिग के कम गहरे नलकूपों को लगाते हैं। मैं जानना

चाहता हूँ कि क्या सरकार ने कभी यह कोशिश की है कि इस तरह के लोगों से, इलाकों से जिन को रिग्ज की जरूरत नहीं है और वे डेढ़ दो सौ फीट का बोरिंग बड़े आराम से पुराने ढंग से ही कर लेते हैं, रिग्ज ले कर उनका इस्तेमाल दूसरी जगह किया जाये ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : It is being used on a large scale. In the case of MP, there was no unit of the State Government. We are trying to help them to set up a unit. They have already set up a survey unit and we have said that one unit of the Exploratory Tubewell Organisation should go and help the State Government.

श्री महाराज सिंह भारती : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हजारों लोग हजारों उथले नलकूप बिना रिग्ज के बना सकते हैं। क्या वहां जो रिग्ज हैं उनको मध्य प्रदेश में ले जा करके या दूसरी जगह ले जा करके काम में लाने की कोशिश की गई है और यह भी सोचा गया है कि उनका इस्तेमाल होना चाहिये क्योंकि वे सब वहां निट्ठले पड़े हैं ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : There is no objection for undertaking these activities in MP.

श्री शशि भूषण वाजपेयी : हमारे देश में बाहर से रिग्ज आई हैं। मध्य प्रदेश की बात मैं जानता हूँ। वहां पचास परसेंट रिग्ज खराब पड़ी हुई हैं। गांधी सैंटिनरी सैलीब्रेसन्स के मौके पर मुझे पता चला है कि यह प्रोग्राम बनाया गया है कि उनको पुनः चलाने की व्यवस्था की जाये ताकि काफी इलाकों में पानी जनता को मिल सके, रिग्ज का सही इस्तेमाल हो। में जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार इस तरफ सोच रही है कि "ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कारपोरेशन" बना करके उसके जरिये रिग्ज की रिपेयरिंग का तथा दूसरी खुदाई का काम करवाया जाये। इसका इन्तजाम सब जगह हो सके, क्या कोई ऐसा इन्तजाम करने का आप सोच रहे हैं ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : If any rigs are not working for want of spares, we are prepared to help the State Government, if they are not locally available. But drinking water does not arise out of this.

श्री ओ० प्र० त्यागी : मध्य प्रदेश की भूमि बहुत उपजाऊ है। परन्तु उस भूमि के नीचे पहाड़ों की चट्टानें हैं और इसवास्ते वहां कुएं बनाना साधारण किसान की पहुँच से बाहर है। अगर वहां बरमों का, कुओं का, नलकूपों का इंतजाम हो जाए तो बहुत बड़ा खाद्य का वहां भंडार प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार की खोज कराने की क्या आपने चेष्टा की है कि इन पहाड़ी चट्टानों को तोड़कर उनके नीचे जो पानी भरा हुआ है, उसको ऊपर लाने के लिये नलकूप लगाये जायें और यह जो काम है इसको सरकारी लेवल पर किया जाये ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I agree that MP has considerable potential for development of tubewells. We are trying to help the State Government, but it is primarily the responsibility of the State Government to set up units in a big way.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा भाग है जिस की नदियां सब तरफ बहती हैं और दूसरे प्रान्तों में 47 लाख एकड़ जमीन को वे सींचती है। नदियों का विवाद भी चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि दूसरे प्रान्तों में पानी जाये और वहां सिंचाई हो। लेकिन इसके साथ-साथ क्या मध्य प्रदेश की जो रिग्ज की मांग है उसको भी पूरा किया जायेगा ताकि वहां भी सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध की जा सकें ?

MR. SPEAKER : The hon. Minister will bear that in mind.

Rehabilitation of Disabled Miners

\+

*1294. SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI P. GOPALAN :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question